

of water huts, taps, gharas, water trolleys etc., have been provided at stations in accordance with the requirements of passenger traffic dealt with. In addition, water coolers have also been provided at important stations. These arrangements are kept under careful watch and are further augmented during summer season by posting of temporary hot weather watermen.

Cool drinking water is also being provided in containers in some First Class corridor type coaches and Third Class sleeper coaches. It is proposed to extend this facility by stages to cover important long distance trains.

Demand by Tamil Nadu Government to provide for representation to States in Parliament on the basis of 1951 Census

6861. SHRI P. RAMAMURTI:
 SHRI UMANATH:
 SHRI K. RAMANI:
 SHRIMATI SUSEELA
 GOPALAN:
 SHRI C. K. CHAKRAPANI:

Will the Minister of LAW AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Tamil Nadu have urged the Central Government to amend the Constitution in order to provide for representation to States in the Parliament on the basis of the 1951 census;

(b) if so, the reason for this demand; and

(c) the reaction of Government thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI M. YUNUS SALEEM): (a) Yes, Sir.

(b) Presumably, the population figures on the basis of 1951 census are most favourable for retaining the maximum number of seats allotted to the State in the House of the People.

(c) The proposal is not justified both on principle and on practical considerations.

पंजाब औद्योगिक विकास निगम द्वारा ट्रैक्टरों का निर्माण

6862. श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :

श्री बंश नारायण सिंह :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री भारत में ट्रैक्टरों के निर्माण के सम्बन्ध में 24 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1771 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब औद्योगिक विकास निगम द्वारा ट्रैक्टर निर्माण करने के प्रस्ताव की इस बीच जांच करा ली है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फल्लरहीन अली अहमद) : (क) और (ख). 1967 में पंजाब औद्योगिक विकास निगम ने बल्गेरिया के मेसर्स एपो मशीन टेक्नोस्पोर्ट के सहयोग से बोलगर (13 अश्व शक्ति) ट्रैक्टरों के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तथापि जब ट्रैक्टर के ट्रैक्टर प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण केन्द्र बुंदनी परीक्षण पर पता चला कि यह भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं रहेगा। अतः पंजाब औद्योगिक विकास निगम ने इस नमूने के ट्रैक्टरों के निर्माण का अपना प्रस्ताव समाप्त कर दिया है।

3 वर्ष की आयु तक के स्कूल के बच्चों के लिये पौष्टिक भोजन

6863. श्री शशि भूषण : क्या बिधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नये बजट प्रस्तावों के अनुसार सरकार द्वारा 3 वर्ष की आयु तक के स्कूल के बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन कराया जायेगा ;

(ख) क्या यह व्यवस्था देश में दूध के उत्पादन को बढ़ाकर किये जाने का प्रस्ताव है अथवा इस उद्देश्य के लिए दूध के पाउडर का आयात करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) खाद्य विभाग द्वारा क्या प्रबन्ध किये गये हैं और इस बारे में सरकार की नीति क्या है ?

बिधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती) फूलरेणु गुहा :
(क) हाँ, श्रीमान । आदिमजातीय क्षेत्रों में 0-3 वर्ष के आयु वर्ग में 5 लाख बच्चों को तथा नगरों की गंदी बस्तियों के 5 लाख बच्चों को पोषण प्रदान करने का एक कार्यक्रम बनाया जा रहा है ।

(ख) जहाँ तक बच्चों को दूध प्रदान करने का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के साथ इस मामले में बातचीत की जा रही है ।

(ग) खाद्य विभाग ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बालाहार तथा कम मूल्य की प्रोटीन खाद्यसामग्री के उत्पादन का एक कार्यक्रम दिया है । बालाहार वनस्पति, प्रोटीन अनाजों तथा दुग्ध पाउडर से बनाया जाता है । बालाहार का उपयोग इस समय केयर की सहायता से स्कूल भोजन प्रदान कार्यक्रम के अधीन पोषण प्रदान करने के लिए किया जा रहा है । 1970-71 तक 50,000 टनी बालाहार का तथा चतुर्थ योजना के अन्त तक लगभग 2.5 लाख टनी बालाहार तक का स्तर प्राप्त करने के लिये क्रमिक आधार पर उत्पादन बढ़ाया जा रहा है ।

C. B. I. Enquiry into Corrupt Practices by Welfare Institutions in Delhi

6864. SHRI V. NARASIMHA RAO :
SHRI MUHAMMAD SHERIFF :

Will the Minister of LAW AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a letter from

the Union Law and Social Welfare Minister to the Delhi Administration on entrusting the Central Bureau of Investigation with an inquiry into various social welfare institutions run by the Administration and indulging in corrupt practices has disappeared from the relevant file ;

(b) whether any inquiry into this matter has been made ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) the name of the official under whose custody the file was kept and the action taken against him ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (DR. (SHRIMATI) PHULRENU GUHA) : (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

नई दिल्ली में एक गैर-सरकारी फर्म को रेलवे भूमि का नियतन

6865. श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री वंश नारायण सिंह :

क्या रेलवे मंत्री नई दिल्ली में एक गैर सरकारी फर्म को रेलवे भूमि के नियतन के बारे में 25 नवम्बर, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 187 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्र 1666 वर्ग गज से बढ़ा कर 2743 वर्ग गज करने की अनुमति देने के लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है ;

(ख) 1942-43 में मैसर्स ओरियंटल एण्ड फरनिशिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के साथ किस प्रयोजन के लिये करार लिया गया था और उसकी शर्तें क्या थीं तथा इस कम्पनी ने करार के उपबन्धों का उल्लंघन करके किस आधार पर कोका कोला कारखाना स्थापित किया ;